भूमण्डलीकरण में उच्च शिक्षा: चुनौतियाँ एवं संदर्भ

डा. विनोद कालरा*

शिक्षा किसी भी आधुनिक, समय, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज का अनिवार्य लक्षण है। इसके अभाव में बहुआयामी प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। एक शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित समाज व शिक्षित राष्ट्र ही प्रगति के मार्ग पर अनवरत यात्रा कर पाने में समर्थ हो सकता है। शिक्षा एक ऐसी बहुआयामी प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र असीमित है इसलिए उसके उद्देश्य भी सीमित नहीं हो सकते। उनमें विविधता का होना अनिवार्य है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए उसके उद्देश्यों का निर्धारण परमावश्यक है। मानव की आत्मा को परिष्कृत करके उसे आत्म साक्षात्कार कराने जैसे शिक्षा के परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत में शिक्षा का उदय उस समय में हुआ जब आज के सर्वाधिक समय, संस्कृत और विकसित कहे जाने वाले राष्ट्र असभ्यता के अंधकार में अपना जीवन मार्ग ढूँढ रहे थे। उपनिषदों में कहा गया है- 'विद्या वह है जिसके द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है।' (विद्ययाविन्दतेऽमृतम्) इसी से मिलता जुलता कथन यह भी है कि 'विद्या वह है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है।' (विद्ययाऽमृतमश्नुते) (सा विद्या या विमुक्तये)। प्लेटो भी मानते हैं कि शिक्षा बालक के शरीर और आत्मा में सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके वह योग्य है। अरस्तू भी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के निर्माण को शिक्षा कहते हैं। समग्रत: शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना उसे सच्चरित्र, सुयोग्य नागरिक बनाना एवं सम्पूर्ण मानव बनाना है।

आज प्रत्येक राष्ट्र में उच्चशिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, विद्वान, साहित्यकार, नेता, कवि, दार्शनिक, लेखक-आलोचक उच्च शिक्षा के प्रांगण से ही उत्पन्न होते हैं। उच्चकोटि के सत्यान्वेषण के लिए विश्वविद्यालय ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जो ज्ञान के क्षेत्र को विस्तृत बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। सम्पूर्ण विश्व की भाँति भारत में भी प्राथमिक शिक्षा को आधारशिला के रूप में तथा उच्च शिक्षा को मुकुट के रूप में स्वीकार किया गया है। जहाँ तक भारत में उच्चशिक्षा की व्यवस्था एवं विकास का प्रश्न है तो इसे सामान्यत: वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम, ब्रिटिश तथा स्वन्तन्त्रता के उपरान्त के काल क्रम में विभाजित कर विवेचित किया जा सकता है।

स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा से लेकर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं और शिक्षा का क्षेत्र न केवल विस्तृत हुआ अपितु बहुआयामी भी हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद से ही भारत में शिक्षा सम्बन्धी नीतियों, शिक्षा की संरचना शिक्षण पद्धतियों आदि सभी क्षेत्रों में सुधार एवं विकास के लिए अनेक सार्थक प्रयास किए जाते रहे हैं। शैक्षिक असमानताएं एवं शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाएं भी निर्धारित की गई हैं। आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की व्यावहारिकता और उपादेयता को निश्चित करने के लिए समयानुसार विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन, शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा में गुणात्मक अभिवृद्धि के लिए विशिष्ट संस्थानों एवं विशिष्ट संगठनों की स्थापना, वर्ग एवं क्षेत्र की आवश्यकतानुसार विशिष्ट कार्यक्रमों, योजनाओं का निर्धारण और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं।

यदि अतीत की ओर झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि भारतीय उच्च शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव कोई नया नहीं है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर दृष्टिपात करने से उस पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावों के प्रथम स्पर्श को स्पष्टत: अनुभव किया जा सकता है। बात वर्तमान परीक्षा-प्रणाली की हो या स्नातक स्तर की शिक्षा की या फिर विश्व-विद्यालय स्तर की योजनाओं की-ब्रिटिश शिक्षा का प्रभाव सभी पर स्पष्ट लक्षित होता है। आई.आई.टी. के सभी पैटर्न यू.एस. के तकनीकी संस्थानों के पैटर्न पर आधारित हैं। अपनी स्थापना

*अध्यक्षा, स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, कन्या महाविद्यालय, जालन्धर शहर

से लेकर आज तक ये संस्थान विदेशों का अभी भी अनुकरण कर रहे हैं। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त अध्ययन केन्द्र (IGNOU) यू.के.के ओपन यूनिवर्सिटी की अवधारणा पर आधारित हैं। यहां तक कि रवीन्द्र नाथ टैगोर जोकि उच्चकोटि के अन्तर्राष्ट्रीयता वादी थे, उन्होंने भी पूर्व और पश्चिम का समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से, शिक्षा द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए 'विश्व भारती' विश्वविद्यालय की स्थापना की। 'बौद्धिक धन-सभी के लिए' की धारणा को लेकर चलने वाला 'विश्व भारती' पाश्चात्य देशों के लिए ज्ञान के नवीन द्वार खोलता है। अत: भूमण्डलीकरण या वैश्वीकरण की अवधारणा अत्यन्त प्राचीन है।

भूमण्डलीकरण अन्तर्राष्ट्रीय ढांचे पर भारतीय शिक्षा के गठजोड़ समन्वय का नाम है। इस दोहरी शिक्षा ने बहुआयामी बनने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा स्तर के अतिरिक्त अनेक सीमाओं को पार कर लिया है। वैश्विक रूप से व्यवस्थित होने के लिए शिक्षा का संसार निरन्तर सिमटता जा रहा है और इस क्षेत्र में वैश्वीकरण की अवधारणा परम्परा और आधुनिकता के बीच सेतु का काम करती दिखाई देती है।

वैश्वीकरण के इस दौर में आर्थिक क्षेत्र की सफलता के बाद वाणिज्य मंत्रालय की निगाह अब उच्च शिक्षा व्यवस्था पर है। उच्च शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) की सेवाओं के तहत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलने का इच्छुक वाणिज्य मंत्रालय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने संस्थान खोलने की अनुमति चाहता है जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके विपक्ष में खड़ा है क्योंकि उच्च शिक्षा इसी के अन्तर्गत आती है। चिन्ता की बात यह है कि वाणिज्य मंत्रालय उच्च शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने की अपेक्षा उसे व्यापार योग्य वस्तु बनाने के पक्ष में है। यह भी एक विडम्बना है जिस विषय का नेतृत्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को करना चाहिए था, उस का नेतृत्व वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय का तर्क है कि भारत में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की मांग तीव्रता से बढ़ती जा रही है जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालय पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे, उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने और सीटें बढ़ाने के निर्णय के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों को अपनी ढांचागत सुविधाएं बढ़ाने के लिए करोड़ों रूपयों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे में केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग के अनुरूप नए विश्वविद्यालय और संस्थान खोलना संभव नहीं है। इस कमी को निजी क्षेत्र एवं विदेशी विश्वविद्यालय पूरा कर सकते हैं। तीसरा तर्क यह है कि भारत के लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर विदेशों की और आकर्षित हो प्रस्थान कर रहे हैं। इस तरह से भारत से प्रतिवर्ष करोड़ों डालर की देशी मुद्रा विदेशों में जा रही हैं। यदि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति प्रदान की जाए तो विदेशी मुद्रा की बचत तो होगी ही, बिना विदेश गए गुणवतत्ता युक्त शिक्षा (Quality Education) भी प्राप्त हो सकेगी। मंत्रालय यह दावा भी करता है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा भारत में परिसर खोलने से राष्ट्र के अपने विश्वविद्यालयों को भी लाभ होगा। प्रतियोगिता के कारण उनका स्तर भी ऊँचा होगा।

परन्तु पिछले दो दशकों से विश्व बैंक के दबाव में उच्च शिक्षा के बजट में लगातार कटौती की जा रही है। परिणाम यह हुआ है कि कुछेक को छोड़कर अधिकांश विश्व विद्यालयों का शैक्षणिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। वे सिर्फ डिग्रियां बांटने का केन्द्र बनकर रह गए हैं। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के विश्वविद्यालयों के मलबे पर निजी शैक्षणिक संस्थानों के तीव्रतम विकास से जहां उच्चशिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है वहीं निजीकरण की व्यवस्था अनुबन्ध प्रणाली का पर्याय बनती जा रही है। निजीकरण वैश्वीकरण के साथ जुड़ती हुई एक अन्य अवधारणा हैं। विश्व बैंक, IMF, WTO और GATS भारत की उच्च शिक्षण संस्थाओं पर शिक्षा के निजीकरण के लिए दबाव डाल रही है. जिससे पास खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो। यदि ऐसा हुआ तो फिर उच्च शिक्षा के आयात-निर्यात पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकेगा। विदेशी निजी संस्थान भारत में अपनी

शाखाएं खोलेंगे, प्रमाणपत्रों, उपाधियों का बेरोकटोक आदान प्रदान होगा। इन विश्वविद्यालयों की मान्यता से भारतीय विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता भी बाधक हो सकती है।

प्रश्न यह है कि क्या विदेशी विश्वविद्यालयों के आने से स्थिति बदलेगी ?

यह सत्य है कि सूचना प्रौद्योगिकी 21वीं सदी में भूमण्डलीकरण का एक महान अवदान है। सूचना प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत कम्प्यूटिंग, टेलिकम्यूनिकेशन और माइक्रोइलेक्ट्रानिकी ने भारत में उच्च शिक्षा के संस्थान में आधुनिक अध्ययन-अध्यापन एवं शोध के क्षेत्र में विशेष सहायक तत्व रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अभाव में भारतीय उच्च शिक्षा काफी पीछे रह जाती है। अध्यापक एवं विद्यार्थी शिक्षण की पारम्परिक चार दीवारी से बाहर निकलकर, भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण कर एक नवीनतम साइबर संसार के माध्यम से शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने तार्किकता, वैचारिक योग्यता, निर्णयात्मक क्षमता, आत्म-विश्लेषण, मूल्यपरक तार्किक एवं वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में नूतन ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित की हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा के वैश्विक प्रयोग के कारण भी उच्च शिक्षा में, अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्र में प्रभावी परिवर्तन आया है। आज का मनुष्य केवल मुद्रित सामग्री का ही मोहताज नहीं है। तकनीकी सुविधाओं ने विश्व के प्रत्येक कोने में शिक्षा के प्रसार में अभिवृद्धि की है। इस प्रसार के बावजूद एक खतरा उच्च शिक्षा पर मंडरा रहा है। सच यह है कि राज्य अपनी मूलभूत जिम्मेदारी से भाग रहा है। इसके माध्यम से वह निजी क्षेत्र और विदेशी सेवा प्रदाताओं के लिए जगह बना रहा है। यदि सरकार ईमानदारी से अपना वचन पूरा करे तो उच्च शिक्षा की मांग को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। सूचना और प्रौद्योगिकी भारतीय उच्च शिक्षा के लिए तभी लाभप्रद हो सकती है जब भारत की साधारण जनता तक इसकी पहुँच हो और इसमें संदेह है क्योंकि भारतीय विद्यार्थी आर्थिक रूप से असम्पन्न होने के कारण इस सुविधा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। जब तक यह तकनीकी सुविधा सर्वसाधारण तक नहीं पहुँचेगी, सामाजिक असमानता का संकट गहरा जाएगा। सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना होगा। ताकि सुविधा अधिकतम विद्यार्थियों को प्रदान की जा सके अन्यथा भूमण्डलीकरण के प्रभाव भयंकर हो सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों का आना भारतीय शिक्षा की स्थिति को और अधिक खराब ही करेगा क्योंकि विदेशी विश्वविद्यालय जो कि मात्र लाभ कमाने एवं भारत में स्थायी रूप से स्थापित होने के उद्देश्य से आने के प्रयास में हैं, भारतीय शिक्षण संस्थानों के अनुभवी एवं सुयोग्य अध्यापकों को अत्यधिक वेतनमान का लोभ देकर अपनी ओर खींच ले जाएंगे और भारतीय विश्वविद्यालय कानून के स्तर पर भी इनका मुकाबला कर पाने में असमर्थ होंगे। परिणाम यह होगा कि भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों का स्तर इन अनुभवी व योग्य अध्यापकों के अभाव में और भी गिर जाएगा। उन्हें भी उच्च वेतनमान एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाओं में बढ़ौतरी के लिए विद्यार्थियों की फीस बढ़ानी होगी और फिर उच्च शिक्षा केवल उच्च एवं धनाढ्य वर्ग की बपौती रह जाएगी और गरीब और कमोर वर्ग शिक्षित होने का स्वप्न मात्र देखता रहेगा। यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा नहीं करते तो फिर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की भाँति उच्चशिक्षा में भी दोहरी शिक्षा नीति पैदा होगी। और भारत इस स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं होगा।

यह ठीक है कि भारत में विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इन्जीनियरिंग संस्थाओं, प्रबन्धन संस्थाओं आदि सभी स्तरों पर जहां संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, वहीं इन संस्थाओं में शिक्षकों एवं शिक्षार्थियों की संख्या भी बढ़ी है पर क्या इन शिक्षार्थियों की शिक्षा इन्हें रोजगार देने में सहायक सिद्ध हुई हैं? सैद्धान्तिक एवं उद्देश्यविहीन शिक्षा, बोझिल पाठ्यक्रम, अवैज्ञानिक एवं अविश्वसनीय परीक्षा प्रणाली, प्रत्येक स्तर पर संसाधनों की कमी जैसी अनेक समस्याएं शिक्षाविदों शिक्षकों, प्रशासकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों के समक्ष चुनौती बनकर खड़ी हैं। आयोग और समितियों के गठन मात्र से, योजनाएं बना कर फाइलों में बन्द कर देने से, शिक्षा के क्षेत्र में नाममात्र वित्तीय परिव्यय बढ़ा देने से इस क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं का

समाधान नहीं हो पाएगा। उच्च शिक्षा का विदेशीकरण ज्ञानार्जन, समाज सेवा और राष्ट्रनिर्माण के लिए खतरे की घण्टी है। अध्ययन-अध्यापन व शोध के क्षेत्र में भारतीय विश्व विद्यालयों का मुख्य लक्ष्य, पारम्परिक, अधुनातन एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करना है। भारतीय उच्च शिक्षा में गुरुकुल के वैदिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है ताकि हम अपनी सांस्कृतिक सम्पदा, अपने रीति-रिवाज अपनी आध्यमिकता को सुरक्षित रख सकें। निजीकरण से उच्च शिक्षा में समाज एवं जन हित से सम्बन्धित सोच को कर्मशियल हित में परिवर्तित होने में समय नहीं लगेगा।

भारत पर वितीय संकट वर्षों से गहरा रहा है और यही संकट उच्च शिक्षा के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। धनाभाव के कारण शिक्षा की गुणवत्ता भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। भारत में शिक्षा के निजीकरण का स्वागत तभी हो सकता है जब विश्वविद्यालयों के मध्य कुछ वैचारिक सामूहिक प्रयास किए जाएं। निजी संस्थान भारतीय विश्वविद्यालयों की सहायतार्थ आगे आएं। यदि विदेशी योजना ऐसी हो जो शैक्षिक आदान प्रदान से भारत को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प हों तभी भारत में शिक्षा के निजीकरण का स्वागत होगा। शिक्षा के बाजारीकरण के लिए निजीकरण कभी अभिनंदित नहीं होगा। भारतीय विश्वविद्यालयों को वित्तीय संकट से बचाने का जो महत्वपूर्ण कार्य भारत शिक्षा कोश द्वारा किया गया है वह नि:संदेह सराहनीय प्रयास है। वैयक्तिक समूहों/संगठनों, केन्द्रीय व रा%य सरकारों, प्रवासी भारतीयों और विदेशी संस्थाओं के अनुदान से अनुप्राणित यह कोश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वरदान सिद्ध हुआ है। निजी वितीय अनिवार्यता के चलते उद्योग, विश्वविद्यालय गठबंधन, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, भारतीय उच्च तकनीकी आयोग की वितीय अनुदान देने की वचन बद्धता उच्चशिक्षा के क्षेत्र में आने वाले संकट को काफी हद तक कम कर सकती है। उपकरणों के लिए राशि प्रदान कर, विद्यार्थियों के लिए वजीफा, तथा ढांचांगत सुविधाओं से पूरे शिक्षा क्षेत्र में महान परिवर्तन आ सकता है।

वैश्वीकरण का प्रभाव शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी देखा जा सकता है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में विश्व स्तर पर नवीनता एवं एकरूपता लाने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के अनुकरण पर भारतीय उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम निर्धारित एवं निर्मित किया जा रहा है। यद्यपि विश्व के तीव्रता से परिवर्तित होते परिदृश्य एवं उच्च शिक्षा में अन्तर्ज्ञानानुशासनात्मक प्रवृति को सशक्त करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्मित किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी की विश्लेषणात्मक एवं आलोचतनात्मक सोच अग्रसर हो। तथापि वैश्विक उच्च शिक्षा में विश्व के दूसरे स्थान पर रहने वाले भारत की विश्व विद्यालय स्तर की शिक्षा लगातार विस्तार, गिरते स्तर, सीमित साधनों और राजनीतिक हस्तक्षेप के संकट का सामना कर रही है।

नवीनता और पारस्परिक सहभागिता वैश्वीकरण का एक सुखद पहलू है। विद्यार्थी व संकाय का आदान प्रदान, शोध क्षेत्र में सामूहिक भागीदारी के रूप में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों बीच सहभागिता का यह सम्बन्ध स्तुत्य है। परन्तु विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों एवं उच्चशिक्षा पर अपनी व्यवस्था का आरोपण अनुचित एवं अस्वीकार्य हैं। अत: भारतीय उच्चशिक्षा पर वैश्वीकरण का मिश्रित सा प्रभाव प्रतीत होता है। वैश्विक परिदृश्य में प्रगतिशील राष्ट्रो में प्रति स्पर्धा की क्षमता अपेक्षाकृत कम है। वैश्वीकरण एव गम्भीर मुद्दा है और राष्ट्र निर्माण और सामाजिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में इस पर गम्भीर विचार विमर्श अपेक्षित है। इस संदर्भ में व्याप्त बुराइयों और कठिनाइयों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर दीर्घकालीन नियोजन, प्रशासकीय एवं राजनीतिक दृढ़ संकल्प शक्ति, जन सहयोग व जन कल्याण की भावना से से सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने उतरदायित्व का निर्वाहण करने से ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। वैश्वीकरण का अर्थ भ्रातृत्व, पारस्परिक समझ, सांस्कृतिक-सामाजिक समन्वय, संयम, सहनशीलता, परस्पर सम्मान की भावना से अनुप्राणित होना है। अत: इस दिशा में जल्दबाजी से नहीं बल्कि सहजता व सही सोच से कदम बढ़ाने की अवश्यकता है। समुचित वातावरण के निमणि से 'विश्वगाँव' की परिकल्पना साकार हो सकेगी और हम विश्वस्तरीय नागरिकों का निर्माण करने में सक्षम हो सकेंगे।